पीएम-सूरज पोर्टल

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- पीएम सूरज पोर्टल एक राष्ट्रीय पोर्टल है, जो सामाजिक उत्थान और रोजगार पर आधारित और जनकल्याण के लिए है। इस पोर्टल के जरिए ऋण सहायता स्वीकृत की जाएगी। इससे पात्र लोगों को ऋण लेने में सुविधा मिलेगी।
- इस पोर्टल के जरिए लोग आसानी से लोन ले पाएंगे, जिसमें 15 लाख रुपये तक के बिजनेस लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
- इससे बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इसी पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकेगा।
- इस पोर्टल का उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान और सशक्तिकरण करना है। योजना अंतर्गत ऋण मुहैया कराया जाएगा।
- पीएम सूरज पोर्टल के अंतर्गत पात्र लोगों को बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थान और अन्य संगठनों के जरिए ऋण दिया जाएगा।

भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन (MoU)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच पेट्रोलियम, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इसके तहत भारत से भूटान को पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक (पीओएल) और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया|
- इसका उद्देश्य विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में, किसी भी लैंगिक, वर्ग या आय पूर्वाग्रह के बिना, भूटान के साथ बेहतर आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के जरिये भारत और इसके नागरिकों को लाभ पहुंचाना है। समझौता ज्ञापन हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा और भूटान को पेट्रोलियम उत्पादों की सुरक्षित और दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
- सुरक्षा के क्षेत्र में भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (बीएफडीए), स्वास्थ्य मंत्रालय, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर होने से दोनों पड़ोसी देशों के बीच कारोबार में सुगमता आएगी।
- भारत से उत्पादों का निर्यात करते समय बीएफडीए एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन के प्रमाण के रूप में एक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करेगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन मिलेगा और दोनों पक्षों के लिए अनुपालन लागत कम होगी।
- इसके अलावा ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई है।
- भारत का लक्ष्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित स्टार लेबलिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देकर घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में भूटान की सहायता करना है। भूटान की जलवायु स्थिति के अनुरूप बिल्डिंग कोड तैयार करने में भारत के अनुभव के आधार पर मदद की जाएगी। ऊर्जा लेखा परीक्षकों के प्रशिक्षण को

संस्थागत बनाकर भूटान में ऊर्जा पेशेवरों के एक समूह के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

- यह समझौता ज्ञापन विद्युत मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय (एमईए) और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के परामर्श से तैयार किया गया है। यह समझौता ज्ञापन भारत और भूटान के बीच ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण से संबंधित सूचना, डेटा और तकनीकी विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को सक्षम करेगा। इससे भूटान को बाजार में ऊर्जा कुशल उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह समझौता ज्ञापन ऊर्जा दक्षता नीतियों और ऊर्जा दक्षता अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में सहयोग का विश्लेषण करेगा।

भारत - भूटान संबंध

- भारत और भूटान के बीच 1949 में मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और फरवरी 2007 में इसे संशोधित किया गया था। इस संधि के तहत दोनों देशों से एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आह्वान किया गया। संधि ने मुक्त व्यापार और प्रत्यर्पण प्रोटोकॉल भी स्थापित किए।
- भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और उसका प्रमुख निर्यात गंतव्य है। भूटान की जलविद्युत क्षमता देश के लिये राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है और भारत ने भूटान की जलविद्युत परियोजनाओं को विकसित करने में सहायता देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।
- भूटान और भारत प्रबल सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं और दोनों देशों के बीच जीवंत सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है। कई भूटानी तीर्थयात्री भारत में पवित्र बौद्ध स्थलों की यात्रा करते हैं। भारत ने भूटान को उसकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहायता प्रदान की है और कई भूटानी छात्र उच्च शिक्षा के लिये भारत आते हैं।
- दोनों देश एक खुली सीमा साझा करते हैं (वीजा की आवश्यकता नहीं है) जिसमें काम, पर्यटन, खरीदारी, चिकित्सा देखभाल आदि के लिए दोनों दिशाओं में यात्रियों का नियमित आदान-प्रदान होता है।
- भूटान भारत के साथ 600 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है। भूटान भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक साझेदार है क्योंकि यह चीन और भारत के बीच एक बफर है।
- भारत ने भूटान को रक्षा, अवसंरचना और संचार जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान की है, जिससे भूटान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में मदद मिली है। वर्ष 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरोध के दौरान भूटान ने चीनी घुसपैठ का मुक़ाबला करने के लिये भारतीय सैनिकों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण और सतत पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भूटान को सहायता प्रदान की है।

भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को सशक्त बनाने तथा संचालन के लिए सहयोग से संबंधित भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को मंजूरी दी गई|
- इस अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना एवं बंदरगाहों, समुद्री तथा लॉजिस्टिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है।
- इस समझौते में दोनों देशों के बीच सहयोग की विस्तृत रूपरेखा है। यह सहयोग पारस्परिक रूप से सहमत सिद्धांतों, दिशानिर्देशों और दोनों देश के अधिकार क्षेत्रों के तहत प्रासंगिक नियमों एवं विनियमों के अनुरूप समझौतों के एक समुच्चय पर आधारित होगा।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) क्या है?

- भारत -मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) एक नियोजित आर्थिक गलियारा है जिसका उद्देश्य एशिया, फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है ।
- यह गलियारा भारत से संयुक्त अरब अमीरात , सऊदी अरब , जॉर्डन , इज़राइल और ग्रीस के माध्यम से यूरोप तक प्रस्तावित है ।
- गौरतलब है कि 10 सितंबर 2023 को भारत , संयुक्त राज्य अमेरिका , संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस , जर्मनी , इटली और यूरोपीय संघ की सरकारों द्वारा नई दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए थे ।
- इसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना है, जिसमें रेल, सड़क तथा समुद्री मार्ग शामिल हैं। गलियारे में एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा केबल भी शामिल होंगे।
- इससे व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाकर एशिया, यूरोप तथा मध्य पूर्व के एकीकरण में बदलाव आने की आशा है।

- यह परियोजना रेल और शिपिंग नेटवर्क के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच परिवहन और संचार लिंक को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी और इसे चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के जवाब के रूप में देखा जाता है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा की है|

संबंधित प्रमुख बिंदु

- यह योजना कुल 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ यह योजना आगामी 01 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक लागू की जाएगी|
- इसका उद्देश्य देश में हरित गतिशीलता को और अधिक बढ़ावा देने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास को को बढ़ावा देना है|
- यह योजना देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को अपनाने में और तेजी लाने के लिए शुरू की गई है| यह योजना इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (ई-2 डब्ल्यू) और तिपहिया वाहन (ई-3 डब्ल्यू) पर लागू होगी| इसके अतिरिक्त व्यावसायिक उपयोग के अलावा, निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाली पंजीकृत ई-2 डब्ल्यू भी योजना के अंतर्गत पात्र होगी।
- इस योजना का लक्ष्य 3,33,387 दो पहिया (ई-2 डब्ल्यू) और 13,590 रिक्शा एवं ई-कार्ट सहित 38,828 तिपहिया (ई-3 डब्ल्यू) और एल 5 श्रेणी में 25,238 तिपहियों (ई-3 डब्ल्यू) सहित 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करना है।
- यह योजना देश में एक कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीले ईवी विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देती है, जिससे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा मिलता है।
- इस उद्देश्य के लिए, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) को अपनाया गया है जो घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करता है और ईवी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करता है। इससे मूल्य श्रृंखला में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी सृजित होंगे।

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP)

- इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा हासिल करने के लिए भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2013 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करके वर्ष 2020 से वर्ष-दर-वर्ष हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था|
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य वाहन निर्माताओं, चार्जिंग अवसंरचना कंपनियों, फ्लीट ऑपरेटरों, सेवा प्रदाताओं सहित संपूर्ण ई-मोबिलिटी पारितंत्र को प्रोत्साहन देना है।
- एनईएमएमपी के तहत, सरकार ने वर्ष 2015 में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम इंडिया) योजना शुरू की है।

10वीं भारत-इटली संयुक्त रक्षा समिति की बैठक

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 13 मार्च 2024 को 10वीं भारत-इटली संयुक्त रक्षा समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई|

संबंधित प्रमुख बिंदु

- भारत के रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमने और इटली के रक्षा महासचिव और राष्ट्रीय आयुध निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल लुसियानो पोर्टोलानो ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।
- बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, औद्योगिक और सैन्य सहयोग के व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने इंडो-पैसिफिक और सुरक्षा स्थितियों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
- इस बैठक का विशेष ध्यान दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने पर था। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को गहरा करने के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करने वाले इस समझौते के साथ, दोनों पक्षों ने भारत में सह-उत्पादन सहित संयुक्त परियोजनाओं के लिए दोनों देशों की रक्षा कंपनियों को एक साथ लाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की।
- गौरतलब है कि दोनों देशों ने अक्टूबर 2023 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की इटली यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

भारत-इटली संबंध

- भारत और इटली के बीच राजनीतिक संबंध वर्ष 1947 में स्थापित हुए। मार्च 2023 में भारत तथा इटली ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी तक बढ़ाया।
- इटली यूरोपीय संघ में भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच 14.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया।
- इटली को भारतीय से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएँ तैयार वस्त्र, चमड़ा, लौह अयस्क, मोटर वाहन, कपड़ा, रसायन, रत्न एवं आभूषण हैं। जबकि इटली से आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएँ सामान्य और विशेष प्रयोजन यांत्रिकी, यंत्र उपकरण, धातुकर्म उत्पाद तथा अभियांत्रिकी संबंधी वस्तुएँ हैं।
- भारत-इटली सैन्य सहयोग समूह (India-Italy Military Cooperation Group- MCG) दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिये स्थापित एक मंच के रूप में कार्य करता है। वहीं मिलान - भारत और इटली के बीच एक द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है।
- इटली और भारत के बीच रणनीतिक संबंध हैं, दोनों देश ग्लोबल साउथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इटली "विस्तारित" भूमध्य सागर के केंद्र में है, जो इंडो-पैसिफिक के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है, जबकि भारत वैश्विक दक्षिण और पश्चिमी देशों के बीच एक आदर्श पुल का प्रतिनिधित्व करता है।

70th BPSC TARGET 2024
ESSAY PROGRAM
हिंदी माध्यम | ENGLISH MEDIUM MODE: Offline & Online
STARTING FROM 15th & 22nd MARCH 2024
ADMISSION OPEN upto 50% OFF*
Course Features:
Focus on Philosophical topics PYQ based discussion 15 Tests
EXCLUSIVE BATCH FOR
70th BPSC MAINS
हिंदी माध्यम | ENGLISH MEDIUM MODE: Offline & Online
ADMISSION OPEN
15 New Batch Starting from MARCH 2024
upto 50% OFF